के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई सफलता नहीं मिली है ;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या भविष्य में सरकार अपनी वर्तमान कार्य योजना में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार रखेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) हालांकि सर्वेक्षण में लोगों के स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच की जानी थी लेकिन जांच शरीर के वजन तथा ऊंचाई तक ही सीमित रह गई। इस सर्वेक्षण में ऐसे प्रश्नों जैसे क्या विद्यमान खून और विटामिन की कमी को दूर करने में भी सुधार हुआ था एवं क्या अस्वस्थता दर और शिशु मृत्यु दर में परिवर्तन हुआ है, का उत्तर नहीं मिल सका । इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सफलता नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2811. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेकों बड़े औद्योगिक घरानों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु अनेकों परियोजनाएं सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस बड़े औद्योगिक घरानों ने कौन-कौन सी परियोजनाएं सरकार को अगस्त, 1988 तक भेजी हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के समय इस क्षेत्र में कार्यरत लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण का ध्यान रखेगी, यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मैसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि., गोआ ने हिमाचल प्रदेश में स्थित सिरमौर जिले में खुंगी, शतावर आदि की खेती करने और वहां प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह 100% निर्यात-उन्मुख यूनिट होगा और इस प्रस्ताव में मैसर्स पिल्लसबरी कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त है ।

(ग) सरकार की नीति हमेशा यथावश्यक लघु उद्योगों के लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित कर इनके हितों की सुरक्षा करने की रही है ।

बंधुआ मजदूरों को सहायता

2812. **श्री राम जेठमलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने से लेकर उन्हें पूर्ण रूप से बसाने के बीच की अवधि के दौरान उन्हें जीवनयापन हेतु सहायता देने की कोई योजना बनायी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखने के आरोप में गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में कितने लोगों को पकड़ा गया और कितनों को दंड दिया गया ?